हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्षः 10 अंकः 339 लखनऊ, सोमवार 15 सितम्बर 2025 पृष्ठः 04 मूल्यः 01 रूपये

मुख्यमंत्री योगी ने आम जनता से यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के मांगे सुझाव

-अब तक डेढ़ लाख फीडबैक आए

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध यूपी के निर्माण के लिए जनता से सुझाव देने की अपील की है। उन्होंने रविवार को प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में यूपी आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश/2047 के लक्ष्य को पाने के लिए आपके अमूल्य सुझाव महत्वपूर्ण हैं। ये सुझाव समर्थ उत्तर प्रदेश की संकल्पना की पूर्णता में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। सीएम ने कहा कि हम सब मिलकर अपने विचारों व सुझावों से एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। प्रदेशवासी अपने सुझाव क्यूआर कोड अथवा samarthuttarpradesh.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। बता दें कि रविवार तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में नोडल

अधिकारियों एवं प्रबुद्धजनों ने भ्रमण कर छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संगठनों, मीडिया और आम जनमानस से संवाद किया। जिसमें बीते आठ वर्षों की विकास यात्रा साझा करने के साथ भविष्य की दिशा तय करने हेतु रोडमैप पर चर्चा और फीडबैक प्राप्त किया गया। वहीं पोर्टल पर अब तक करीब डेढ़ लाख से अधिक फीडबैक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से करीब एक लाख फीडबैक ग्रामीण क्षेत्रों से, जबकि बाकी नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। इन जिलों से अधिक सुझाव कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, जौनपुर, बलरामपुर, प्रतापगढ़ और फिरोजाबाद जैसे जनपदों से सबसे अधिक भागीदारी रही। इन जिलों से कुल 53,996 से अधिक फीडबैक प्राप्त हुए, जो दर्शाता है कि जनता इस अभियान को गंभीरता से ले रही है।

बसपा में बड़ा फेरबदल, मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को सौंपी अहम जिम्मेदारी

संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल करते हुए अपने समधी और वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर उन्हें चार अहम राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में पार्टी में वापसी करने वाले अशोक सिद्धार्थ अब छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और गुजरात में संगठन को मजबूत करेंगे। इससे पहले इन राज्यों की जिम्मेदारी रणधीर सिंह बेनीवाल के पास थी। अब बेनीवाल को सेक्टर-चार का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी अभी तक डॉ. लालजी मेधांकर संभाल रहे थे। श्री मेधांकर को नए फेरबदल के तहत

सेक्टर-पांच का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, सेक्टर-छह अब पूर्व विधायक अतर सिंह राव संभालेंगे। यह जिम्मेदारी अब तक पूर्व विधायक धर्मवीर सिंह के पास थी। सेक्टर-एक और सेक्टर-दो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेक्टर-एक पूर्व सांसद रामजी गौतम के पास रहेगा, जबकि सेक्टर-दो की जिम्मेदारी पूर्व सांसद राजाराम के पास बनी रहेगी। मायावती ने संगठनात्मक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए देश को छह सेक्टरों में विभाजित किया है। हर सेक्टर में तीन से चार राज्यों को शामिल किया गया है। इन सेक्टरों के कार्यों की समीक्षा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद करेंगे।

ई-कॉमर्स सेक्टर 2028 तक 160 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद

एजेंसी

लखनऊ। आज के डिजिटल युग में किसी भी कारोबार को ऑनलाइन लाना सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है, खासकर जब भारत का ई-कॉमर्स सेक्टर 2028 तक

160 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। त्योहारों के मौसम में ऑनलाइन मौजूदगी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जब अचानक खरीदारी और आखिरी मिनट के ऑर्डर कई गुना बढ़ जाते हैं। बिना वेबसाइट और डोमेन नाम की बारीकियों को जाने, उसमें निवेश करना निश्चित रूप से थोड़ा डराने वाला हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है।इस त्योहारी सीजन में, गोडैडी भारत भर के छोटे कारोबारियों को डिजिटल बनने और कम कीमत पर-सिर्फ 99 में बड़ा प्रभाव डालने के लिए मजबूत बना रहा है। हर हफ्ते, एक नया डोमेन एक साल की अवधि के लिए 95 प्रतिशत तक की छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सितंबर सुपर सेविंग्स सेल नए ग्राहकों को गोडैडी वेबसाइट पर उसकी उपलब्धता की जांच करने के बाद अपने बिजनेस के अनुरूप डोमेन नाम खरीदने की सुविधा देती है। एक उपयुक्त डोमेन नाम चुनना कई कारणों से एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह लोगों को वेबसाइट के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और ग्राहकों के बीच विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह वेबसाइट को स्कैमर्स और साइबर हमलों से भी सुरक्षित रखता है। अंत में, एक डोमेन नाम यादगार होना चाहिए और विजिटर्स के मन पर एक स्थायी छाप छोड़नी चाहिए।यह ऑफर सीमित समय के लिए है, जो केवल सितंबर के दौरान गोडैडी की आधिकारिक वेबसाइट पर नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। ये छोटे और मध्यम एंटरप्राइजिज के लिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन शुरू करने और इस शुभ त्योहारी सीजन का भरपूर लाभ उठाने का एक बेहतरीन अवसर है।

मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं- पीएम मोदी

एजेंसी

दरांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग जिले में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी सफलता थी और मुझे यहां आकर काफी खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा असम का पहला दौरा है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी सफलता थी। आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर मुझे एक अलग ही पवित्र अनुभूति हो रही है और ये भी सोने पे सुहागा है कि आज इस क्षेत्र

में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। लाल किले से मैंने कहा था, मुझे चक्रधारी मोहन याद आए। मुझे श्री कृष्ण याद आए और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र का विचार लोगों के सामने रखा है। पीएम मोदी ने कहा, हम भारत रत्न सुधाकंठा भूपेन हजारिका का जन्मदिन पहले ही मना चुके हैं। एक दिन पहले मुझे उनके सम्मान में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री ने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का एक वीडियो दिखाया और इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत, असम के गौरव, भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद पंडित नेहरू ने जो कहा, उससे उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी नहीं भरे हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका का जिक्र करते हुए कहा, मुझे कितनी ही गालियां दें, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। लेकिन, जब किसी और का अपमान होता है, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग मुझे बताएं कि क्या भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा निर्णय सही है या गलत? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए किया गया अपमान सही है या गलत? उन्होंने आगे कहा, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं। उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है।

अमित खरे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त, चारा घोटाले का पर्दाफाश करने में रही है अहम भूमिका

एजेंसी

नयी दिल्ली। सरकार ने रविवार को पूर्व नौकरशाह अमित खरे को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया। खरे 12 अक्टूबर, 2021 से प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों का जिम्मा संभाल रहे थे। वह 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' तैयार करने और लागू करने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। खरे की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ''मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने झारखंड कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त) अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दी है।'' कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, खरे की नियुक्ति संविदा आधार पर सचिव रैंक में और समानुरूप वेतनमान के तहत तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी। खरे ने अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों में कई अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। उन्होंने 31 मई, 2018 को भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और बाद में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव तथा उच्च शिक्षा सचिव के रूप में भी सेवाएं दी। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से स्नातक और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नानकोत्तर डिग्री धारक खरे बिहार के 'चारा घोटाले' को उजागर करने में अपनी अहम भूमिका के लिए भी व्यापक रूप से जाने जाते हैं।

संक्षिप्त समाचार

गुरु पूजा एवं भंडारे में कबीर पंथी का उमड़ा संत समाज

संवाददाता

लखनऊ। सदगुरु कबीर जागू आश्रम दसौली पर आज गुरु पूजा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक ऋषि त्रिवेदी के संयोजकत्व में हुये इस कार्यक्रम में काफी संख्या में साधु-संतों सहित विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। जिनमें श्री श्री108 महंत योगेंद्र दास साहेब, महंत अनुराग दास जगदीशपुर गौरैया आश्रम सीतापुर, महंत विचार साहेब मातापुर सीतापुर, आचार्य शिवपूजन दीक्षित, योगाचार्य प्रकाश श्रीवास्तव, अखण्ड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र मौली शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण मिश्रा, राम तिवारी, अखण्ड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय संयोजक पंकज तिवारी शामिल थे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः बीजक पाठ व गुरू पूजा संध्या पाठ,आरती के साथ हुई जिसके उपरांत दोपहर एक बजे से भंडारा प्रसाद वितरण किया गया।

इंडो-नेपाल सीमा पर पटरी पर लौट रही जिंदगी बाजारों में रौनक, व्यापारी खुश

संवाददाता

लखनऊ। इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अब हालात सामान्य हैं। दोनों देशों के नागरिक बिना किसी दिक्कत के सीमा पार कर रहे हैं, जिससे यात्रियों, व्यापारियों में खुशी का माहौल है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद आवागमन सुचारु होना शुरू हुआ था और अब व्यापारिक गतिविधियां भी रफ्तार पकड़ रही हैं। भारतीय वाहनों को नेपाल जाने के लिए कस्टम सेवाएं शुरू होने का इंतजार है।नेपाल पुलिस के अधिकारी उपेंद्र बुढा थोकी के मुताबिक एक-दो दिन में कस्टम कार्यालय का संचालन शुरू होगा।

ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस पर हिंदी भाषी समुदाय को दी बधाई, उनके विकास के लिए किए गए प्रयासों का किया उल्लेख

एजेंसी

कोलकाता। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषी समुदाय को बधाई दी और राज्य सरकार द्वारा उनके विकास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज हिन्दी दिवस है। इस अवसर पर सभी हिन्दी भाषी भाई-बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष हम श्रद्धा के साथ हिन्दी दिवस मनाते हैं। हम सभी भाषाओं के प्रति श्रद्धावान हैं। इस संदर्भ में कहूं तो वर्ष 2011 के बाद से राज्य में हिन्दी भाषी लोगों के विकास के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। जिन क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दी भाषा में बात करते हैं, वहां हिन्दी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। हमने संथाली, कुरुख, कुड़माली, नेपाली, उर्दू, राजवंशी, कामतापुरी, उड़िया, पंजाबी, तेलगु भाषाओं को भी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी है। सादरी भाषा के विकास के लिए भी हम प्रयासरत हैं। सीएम ममता ने कहा, षहिन्दी भाषा के विकास के लिए हिन्दी अकादमी का गठन

किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हावड़ा में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बानारहाट और नक्सलबाड़ी में हिन्दी माध्यम के डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। इसके अलावा कई कॉलेजों में हिन्दी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। उच्च माध्यमिक के प्रश्नपत्र अब हिन्दी में भी उपलब्ध हैं। रवीन्द्र मुक्त विद्यालय के छात्र-छात्राएं हिन्दी भाषा में माध्यमिक परीक्षा दे पा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी भाषी लोगों सहित अन्य लोगों के लिए निशुल्क सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की गई हैं। सीएम ममता ने आगे लिखा, गंगासागर मेले के मद्देनजर उस क्षेत्र में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना विकसित की गई है। हिन्दी भाषी समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए, राज्य सरकार ने छठ पूजा के उपलक्ष्य में दो दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। हिन्दी दिवस पर मेरा अभिनन्दन ग्रहण करें।

लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, टेकऑफ से पहले रुका इंडिगो प्लेन, सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री थे सवार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार (14 सितंबर) को एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट टेकऑफ के दौरान अचानक रनवे पर ही रुक गई। फ्लाइट में कुल 151 यात्री सवार थे, जिनमें समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी शामिल थीं। सूत्रों के मुताबिक, विमान ने रनवे पर तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू किया था, लेकिन टेकऑफ से ठीक पहले तकनीकी कारणों से वह हवा में नहीं उठ सका। हालात को भांपते हुए फ्लाइट के कैप्टन ने सतर्कता दिखाते हुए रनवे के अंतिम छोर से पहले ही विमान को रोक लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। घटना के दौरान विमान में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और घबराहट का माहौल बन गया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंडिगो एयरलाइंस की ओर से बाद में सभी यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिगो की टीम घटना की जांच में जुट गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा तकनीकी खामी के चलते हुआ। हालांकि, इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

राहुल गांधी के वार पर केशव मौर्य का कटाक्ष, बोले-कांग्रेस ने गलत हथियार थमा दिया

संवाददाता

लखनऊ। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा व्यंग करते हुए कहा कि शुरुआत में राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम के स्थान पर छोटा-मोटा पटाखा देना चाहिए था। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के दौरान दिए गए बयान को लेकर रविवार को कटाक्ष करते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स लिखा कि कांग्रेस को अपने मनमौजी नेता राहुल गांधी के हाथों में सीधे एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं थमाना चाहिए था। शुरुआत में उन्हें कोई छोटा-मोटा पटाखा देना चाहिए था। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को अपने रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया को बयान दिया था कि भाजपा के लोग बहुत आंदोलित हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी हुई है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिए हैं। इंतजार कीजिए बहुत जल्द वोट चोरी के और खुलासे आने वाले हैं।

मातृभाषा से बच्चों को वो सिखा सकते हैं, जो उसे कोई पाठ्यक्रम नहीं सिखा सकता : अमित शाह

एजेंसी

अहमदाबाद। भारतीय राजभाषा का भविष्य उज्ज्वल है। आपको अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा बोलना और पढ़ना सिखाना चाहिए। यह आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर बच्चे की सोचने की शक्ति उसकी मातृभाषा में होगी, तो वह उसी भाषा में विश्लेषण, अनुमान और निर्णय लेगा। बच्चे को अपनी पसंद की किसी भी भाषा में पढ़ने दें, लेकिन घर पर केवल अपनी मातृभाषा में ही बात करें। हम उसे उसकी मातृभाषा के माध्यम से वो सिखा सकते हैं जो दुनिया का कोई भी पाठ्यक्रम उसे नहीं सिखा सकता। गृहमंत्री अमित शाह ने यह बात गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रहे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कही। रविवार

से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे गांधीनगर, अहमदाबाद और महेसाणा जिलों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद के नारणपुरा में गुजरात के सबसे बड़े 824 करोड़ की लागत से 1.18 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एक भव्य कार्यक्रम और जनसभा का भी आयोजन किया गया है। इस खेल परिसर का दौरा राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेलों और ऑस्ट्रेलियाई खेल उत्कृष्टता मंच जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है।

संपादकीय

इंजीनियर्स डे महज औपचारिकता

भारत में इंजीनियर्स डे य15 सितंबरद्ध को हर साल मनाया तो जाता है, लेकिन जिस तरह नीति निर्धारण से लेकर शीर्ष प्रबंधन तक आई ए एस काबिज हो गए हैं और अभियंताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया है उससे अब यह महज औपचारिकता तक सीमित रह गया है। इंजीनियरों की समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, उनकी स्थिति और सम्मान को लेकर कई चुनौतियाँ हैं। नीति निर्धारण और शीर्ष प्रबंधन में इंजीनियरों को हाशिए पर रखा जाना एक गंभीर समस्या है, जिसके कई कारण और समाधान हो सकते हैं। आइए इस पर गहराई से विचार करें। भारत में नीति निर्धारण और शीर्ष प्रबंधन में आई ए एस यभारतीय प्रशासनिक सेवाद्ध अधिकारियों का वर्चस्व है। इंजीनियरिंग विभागों में भी गैर.तकनीकी लोग अक्सर नेतृत्वकारी भूमिकाओं में होते हैं, जिससे तकनीकी विशेषज्ञता की अनदेखी होती है। इंजीनियरों को अक्सर ष्कार्यकारीष् के रूप में देखा जाता है, न कि नीति निर्माता के रूप में। इससे उनकी रणनीतिक और नेतृत्वकारी भूमिका सीमित हो जाती है। भारत में आईएएस या प्रशासनिक सेवाओं को सामाजिक रूप से अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है, जिसके कारण इंजीनियरिंग पेशे को कमतर आँका जाता है। विकसित देशों में इंजीनियरों को नीति निर्माण और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, जैसे जर्मनी, जापान, और अमेरिका में, जहाँ इंजीनियरिंग नवाचार और तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते यह दृष्टिकोण अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है।इंजीनियरों को सम्मान दिलाने के लिए संभावित समाधान . नीति निर्माण में इंजीनियरों की भागीदारी बढ़ानारू इंजीनियरिंग विभागों में सचिवालय के शीर्ष पदों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता को अनिवार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए, तकनीकी मंत्रालयों और विभागों में इंजीनियरों को सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर की भूमिकाएँ दी जानी चाहिए ।

इंजीनियरों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, जो उन्हें नीति निर्माण और नेतृत्व के लिए तैयार करें।इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रबंधन, नीति निर्माण, और नेतृत्व कौशल को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आई आई टी और एन आई टी जैसे संस्थानों में नीति विश्लेषण और सार्वजनिक प्रशासन पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इंजीनियरों को वास्तविक नीति निर्माण प्रक्रियाओं से जोड़ा जाए।इंजीनियर्स डे को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर, इंजीनियरों की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना चाहिए। मीडिया, सोशल मीडिया, और सार्वजनिक मंचों पर इंजीनियरों के योगदान को उजागर करना होगा। स्कूल और कॉलेज स्तर पर इंजीनियरिंग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए जाएँ, ताकि समाज में इस पेशे के प्रति सम्मान बढ़े। जर्मनी और जापान जैसे देशों में इंजीनियरों को तकनीकी और नीतिगत दोनों स्तरों पर महत्व दिया जाता है। भारत में भी इंजीनियरों को स्टार्टअप, नवाचार, और नीति निर्माण में प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, इंजीनियरों के लिए ष्टेक्नोक्रेट फेलोशिपष् जैसी पहल शुरू की जा सकती है, जिसमें उन्हें सरकार के साथ नीति निर्माण में काम करने का अवसर मिले। इंजीनियरों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार और सम्मान स्थापित किए जाएँ, जो उनकी तकनीकी और सामाजिक योगदान को मान्यता दें। उदाहरण के लिए, सर एमण् विश्वेश्वरैया जैसे दिग्गज इंजीनियरों के नाम पर पुरस्कार और फेलोशिप शुरू की जा सकती हैं। इंजीनियरिंग संगठनों जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स यइंडियाद्ध को नीति निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त करना चाहिए। सरकार और निजी क्षेत्र में इंजीनियरों के लिए विशेष कैडर बनाए जाएँ, जो उन्हें प्रशासनिक और तकनीकी दोनों भूमिकाओं में अवसर दे। भारत में इंजीनियरों को सम्मान दिलाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, नीति, और सामाजिक धारणा में बदलाव शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल आई ए एस के प्रभा मंडल से बाहर आए और राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका को समुचित महत्व दें। इंजीनियरिंग विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव पदों पर विशेषज्ञ इंजीनियरों की ही तैनाती की जाय। इंजीनियर्स डे को केवल एक औपचारिक आयोजन के बजाय, इंजीनियरों के योगदान को उजागर करने और उन्हें सशक्त बनाने का अवसर बनाया जा सकता है। यदि सरकार, उद्योग, और समाज मिलकर काम करें, तो इंजीनियरों को वह स्थान मिल सकता है, जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।

पानी से नहीं, नीतियों से हारी ज़िंदगी

बार-बार दोहराई गई त्रासदी, बाढ़ प्रबंधन क्यों है अधूरा सपना?

— डॉ सत्यवान सौरभ

हरियाणा में 2025 की बाढ़ कोई अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा नहीं थी। यह वही त्रासदी है, जिसकी पुनरावृत्ति राज्य 1978, 1988, 1995, 2010 और हाल ही में 2023 में झेल चुका है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केवल पिछले दो वर्षों में 657 करोड़ रुपये बाढ़ प्रबंधन पर खर्च किए गए, फिर भी इक्कीस जिलों के सैकड़ों गांव पानी में डूबे रहे, साढ़े चार लाख से अधिक किसानों की छब्बीस लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, हजारों परिवार बेघर हो गए और तेरह लोगों की जान चली गई। हर बार यह सवाल उठता है कि आखिर सरकारें और तंत्र क्यों एक ही गलती बार–बार दोहराते हैं और पिछले अनुभवों से सबक क्यों नहीं लेते। बाढ़ कोई अचानक आई विपत्ति नहीं है, बल्कि एक अनुमानित और बार–बार आने वाला खतरा है। नदियों का उफान, बरसाती नालों का रुख बदलना और निकासी व्यवस्था का ध्वस्त होना ऐसी समस्याएं हैं, जो पहले से ज्ञात हैं और जिनका समाधान वर्षों से टलता आ रहा है। 2023 की बाढ़ के बाद सरकार ने बड़े दावे किए थे कि स्थायी समाधान के लिए ड्रेनेज सुधार, तटबंध मजबूत करने और नालों की गहराई बढ़ाने का काम प्राथमिकता पर होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अधिकांश योजनाएं अधूरी रहीं और जो शुरू हुईं वे भ्रष्टाचार या लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। इस अव्यवस्था का सबसे गहरा असर किसानों पर पड़ा है। खरीफ सीजन की धान, बाजरा और गन्ने जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। औसतन एक किसान को प्रति एकड़ पंद्रह से बीस हजार रुपये का नुकसान हुआ। इसके साथ ही पशुधन की मौतें, घरों के ढहने और बुनियादी ढांचे के टूटने से हालात और बिगड़ गए। उद्योग जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। अंबाला और यमुनानगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों और गोदामों में पानी भर गया, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ और हजारों मजदूर रोजगार से वंचित हो गए। इस स्थिति के पीछे प्रशासनिक लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। हरियाणा सरकार के पास न तो गांव–स्तरीय निकासी योजना है और न ही कोई स्थायी रणनीति। मानसून से पहले नालों की सफाई करने की बजाय दिखावटी काम किए जाते हैं। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम सालों से जाम पड़े हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदियों और नालों का प्रवाह जस का तस है। इसके अलावा सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय निकायों के बीच तालमेल का अभाव स्थिति को और गंभीर बना देता है। हर विभाग अपने–अपने दायरे में काम करता है, लेकिन समन्वय के अभाव में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता। जल प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि बाढ़ पर काबू पाने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति बनाना अनिवार्य है। डॉ. शिव सिंह राठ जैसे विशेषज्ञ स्पष्ट कहते हैं कि नदियों की नियमित ड्रेजिंग, बरसाती नालों का वैज्ञानिक पुनर्निर्माण और गांव स्तर तक जल निकासी प्रणाली का निर्माण ही स्थायी समाधान दे सकता है। पर्यावरणविदों का भी यही तर्क है कि नदियों के तटों पर अनियंत्रित अतिक्रमण और अवैध निर्माण बाढ़ की विभीषिका को और बढ़ा देते हैं। जब तक नदियों को उनका प्राकृतिक बहाव नहीं लौटाया जाएगा, तब तक यह त्रासदी बार–बार लौटकर आती रहेगी। किसानों और आम लोगों की पीड़ा आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। हजारों परिवार महीनों तक राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, महिलाओं और बुजुर्गों की सेहत बिगड़ती है और मजदूर वर्ग बेरोज़गारी का शिकार हो जाता है। इस बार भी छह हजार से ज्यादा गांव पानी में डूबे और करीब अट्ठाईस सौ लोग विस्थापित हुए। कल्पना कीजिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घर–बार से उजड़ते हैं, तो उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति किस हद तक डगमगा जाती होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2010 और 2023 जैसी बड़ी बाढ़ें आ चुकी थीं, तो 2025 में वही गलती दोहराने का औचित्य क्या था। असल कारण साफ हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने इस मुद्दे को कभी चुनावी एजेंडा नहीं बनने दिया। सरकारों का दृष्टिकोण हमेशा अल्पकालिक रहा। हर साल राहत और पुनर्वास पर खर्च होता रहा, लेकिन स्थायी संरचनाओं पर निवेश नहीं हुआ। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी ने हालात और बदतर कर दिए। अगर सचमुच स्थायी समाधान चाहिए तो राज्य को ठोस कदम उठाने होंगे। एक स्वतंत्र नदी प्रबंधन आयोग का गठन करना होगा, जो नदियों और नालों की सफाई, तटबंध निर्माण और निगरानी जैसे काम नियमित रूप से करे। हर पंचायत स्तर पर ड्रेनेज योजना तैयार की जानी चाहिए और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्वानुमान और रीयल–टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना होगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी से नालों की सफाई और तटबंधों की देखरेख सुनिश्चित करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि राहत पैकेज पर अरबों रुपये खर्च करने के बजाय स्थायी ढांचे और संरचनाओं पर निवेश किया जाना चाहिए। दरअसल बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानवीय लापरवाही और नीतिगत असफलता का परिणाम भी है। हरियाणा ने नौ बार बाढ़ झेली, लेकिन हर बार केवल आंकड़े गिनने और वादे करने तक ही बात सीमित रही। किसानों की पीड़ा, उद्योगों का नुकसान और विस्थापित परिवारों की त्रासदी हमें यह बताती है कि अब आधे–अधूरे उपायों से काम नहीं चलेगा। सरकार और समाज को मिलकर व्यापक, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन नीति अपनानी ही होगी, वरना 2027 या 2030 में फिर यही खबर पढ़नी पड़ेगी–"एक और बाढ़, एक और नुकसान और एक और अधूरा वादा।"

पड़ोंसी देशों का हाल और भारत

–प्रेम शर्मा

भारत के करीबी और पड़ोंसी देशों के हाल बेहाल है। म्यांमार में 2021, पाकिस्तान में श्रीलंका में 2022, 2024 में बाग्लादेश और अब नेपाल चुनी हुई सरकार के साथ जो कुछ हुआ वह अचानक नही बल्कि पिछले कुछ अरसे से बढ़ता आक्रोश था। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को जानबचाकर भागते देखा गया, जिनकों पकड़ लिया उन पर हमला कर दिया गया। यानि यह जन आक्रोश जिस सरकारे जानबूझ कर अनदेखी कर रही थी। यह तो सच है कि दुनिया का कोई भी देश वहा की सरकार शत प्रतिशत रोजगार नही दे सकती। बढ़ती आबादी के हिसाब से महंगाई नही रोक सकती, लेकिन वह जो कर सकती है वह भी नही कर रही उपर से भ्रष्टाचार और सरकारी रहनुमाओं के ऐशोआराम से अब जनता दूखी और आक्रोशित है। सरकार की मशीनरी के सामने भले ही दुबकी नजर आती हो लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है तख्ता पलट का रूप सामने आता है। दक्षिण एशिया खासकर भारत के पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता बार–बार दस्तक दे रही है। कभी चुनी हुईं सरकारों को बदल दिया जाता है, तो कभी उनका तख्तापलट हो जाता है। व्यवस्था पत्ते की तरह बिखर जाती है। बीते सालो में म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। अब इसका ताजा शिकार नेपाल बना है। भारत के पड़ोसी देशों में जो कुछ हुआ और हो रहा है वह सामान्य घटनाक्रम नही बल्कि लम्बे अरसे से सुलगता जनाक्रोश है जिसकी वहॉ की सरकारों द्वारा लगातार अनदेखी की गई, इसका परिणाम था कि वहॉ के विपक्षी दलों और कतिपय सरकार विरोधी गुटों ने सुलग रही चिनगारी को हवा दे तो और स्थिति खतरनाक हो गई। इतिहास गवाह है कि लंबे समय तक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कारणों से शोषण झेल रही जनता जब बगावत पर उतर आती है तो वह अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाती है। ऐसे हालात ही क्रांति को जन्म देते हैं। ऐसा ही नेपाल में हुआ जहां सत्ताधारी नेता देश को भूल कर खुद का घर भरने में लग गए। देश के युवाओं का सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब नेपाली सरकार ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का प्रयास करके जले पर नमक छिडकने का काम किया। नेपाल में जो घटनाक्रम हुआ, उससे भारत के नेता भी सबक ले सकते हैं। देश की मूल समस्याओं के समाधान के बजाय गुमराह करने वाले मुद्दों पर राजनीति का नतीजा नेपाल विद्रोह है। वैसे तो नेपाल में हुए घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि नेपाल की सरकार ने बीते दिनों फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगा दिया था। ओली सरकार ने यह बैन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए लगाया लेकिन बैन का यह फैसला किशोर एवं युवा पीढ़ी को पसंद नहीं आया। वह इसके खिलाफ सोमवार को सड़कों पर उतर आई और हिंसक प्रदर्शन किया। हिंसा एवं उपद्रव को देखते हुए ओली सरकार ने सोशल मीडिया से बैन तो हटा लिया लेकिन बैन हट जाने के बाद हिंसक विरोध–प्रदर्शन बंद नहीं हुआ। यानि यह विरोध केवल सोशल मीडिया के वैन होने तक सीमित नही था। क्योकि इसके बाद हिंसक प्रदर्शन और उपद्रव भ्रष्टाचार के खिलाफ था। प्रदर्शनकारी राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों पर उपद्रव और उत्पात मचाने लगे। चुन–चुनकर पूर्व प्रधानमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, नेताओं पर हमले हुए और उन्हें सड़क पर दौड़ाकर मारा–पीटा गया। पूर्व पीएम झालनाथ खनाल की पत्नी को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने संसद और सरकारी इमारतों को फूंक दिया। पीएम केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया और जान बचाकर भागे। इसी तरह करीब एक साल पहले बांग्लादेश में भी हिंसा, उत्पात, आगजनी का नेपाल जैसा ही नजारा देखने को मिला था। आरक्षण, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और विरोधियों को दबाए जाने के खिलाफ बांग्लादेश के छात्रों ने हसीना सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। सरकार विरोधी इस मुहिम में बाद में कट्टरपंथी तत्व भी शामिल हो गए। पांच अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारियों ने हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल कर वहां जमकर उत्पात मचाया। बंग बंधु की प्रतिमा तोड़ दी। अपनी जान बचाने के लिए शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। आठ अगस्त को मोहम्मद युनूस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यहां भी एक चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर दिया गया। म्यांमार भारत के इस पड़ोसी देश में 2021 में सेना ने तख्तालपट कर दिया। यहां तख्तापलट भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। जुलाई 2022 में श्रीलंका में जनता सरकार के खिलाफ हो गई। महंगाई, भ्रष्टाचार और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से हताश और निराश लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वहां तोड़फोड़ मचाया। गोटाबाया को यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। पाकिस्तान में अप्रैल 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से बाहर किया गया। यहां सेना के दबाव में इमरान सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने पर इमरान खान अपनी सरकार बचा नहीं पाए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई। साल 2021 में भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ गया। मई में अमेरिका सेना के अचानक अफगानिस्तान छोड़ने के बाद यहां के प्रांत एक–एक कर तालिबान के कब्जे में आते गए। 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया और राष्ट्रपति अशरफ घानी को देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल के घटनाक्रम के बाद भारत में विपक्षी दलों तथा कतिपय बुद्धिजीवी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे है वह उचित नही है। देश को अस्थिर करने का षड़यंत्र और चुनाव के बहाने जनता को भड़काने का खेल किसी भी तरह से जन और राष्टहित में नही है। बहरहाल देश की जनता बहुत समझदार है, उसे मालूम है कि उसे राष्ट हित और स्वंय हित में किसी भी अराजकता को बढ़वा नही देना है। विरोध दर्ज कराने के कई अन्य तरीके है। भारत के हालात नेपाल जितने खराब नहीं हैं, किन्तु सत्ताधारी और विपक्ष के नेताओं को एहतियात के तौर पर नेपाल से सबक लेना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को जनता को बरगलाने और आन्दोलित करने वालों पर नजर रखनी होगी।

स्वाधीन भारत और संकुचित मानसिकता

–संजीव ठाकुर

स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है, इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत में स्वाधीनता के मायने कितने लोग समझ पाते हैं और कितना इसका सही और सटीक प्रयोग कर पाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा और साक्षरता का उस देश और काल को समझने का एक कारगर हथियार हो सकता है पर भारत में मानसिक स्वाधीनता को समझना भी एक बड़ी समस्या है यह अशिक्षा जनित समस्या बहुत ही विकराल है। हम अभी भी पश्चिमी जगत की शिक्षा, कार्यशैली, विज्ञान एवं चिकित्सा पर संपूर्ण रूप से निर्भर हैं केवल एक शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है जो स्वतंत्र भारत के नागरिकों को स्वाधीनता के महत्व को समझने में सक्षम होगा ।अतः स्वाधीन भारत के स्वतंत्र नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्र नागरिक बनाकर देश के प्रति सजग और सचेत किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है ।एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि ष्एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहींष्पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 78 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्जे से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलाने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस,इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज,स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह संघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताबें लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रेषित हुआ आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है। महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दैव दैव आलसी पुकारा है, तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्मविश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से आगे बढ़ने वाला देश या व्यक्ति या समाज सदैव प्रफुल्लित आत्म विश्वासी तथा विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता है। हमें सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास, छिपी हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त होता है। पराधीन देश सामान्य व्यक्ति सदैव पशु तुल्य होते हैं। जिनका अपना कोई विचार या व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता–राम सहायक उनके होते, जो होते हैं, आप सहायक, हम सबको स्वयं पर भरोसा रखना आत्मबल बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देती रहती हैं।

मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन

–शमशेर खरक

कोई भी देश तभी आत्मनिर्भर बन सकता है, जब वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खुद बनाए। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना इस दिशा में सबसे जरूरी कदम है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश अपने छोटे और कुटीर उद्योगों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। देश की समृद्धि तभी संभव है, जब आयात और निर्यात का संतुलन बना रहे और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम हो। आज वैश्विक दबावों के बीच भारत में स्वदेशी को बढ़ाने की बात जोर–शोर से हो रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है जीएसटी की दरों में कटौती। उनका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है,और जीएसटी में राहत छोटे उद्योगों को सस्ता कच्चा माल और कम लागत देकर इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। मोदी सरकार का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन भी है। जब देशवासी स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं, तो वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने इतिहास, कारीगरी और परंपराओं को भी संजोते हैं। आज,भारतीय उपभोक्ता पहले से अधिक सजग हैं। वे समझते हैं कि हर स्वदेशी खरीदारी एक रोजगार का सृजन करती है और एक आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत करती है। घरेलू उद्योगों को एक पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी भारत का सपना अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के बाद अब सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दी जा रही राहतों के जरिए घरेलू उद्योगों को एक नई उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कुछ आवश्यक घरेलू उत्पादों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की गई है। इसका सीधा लाभ छोटे और मध्यम दर्जे के स्वदेशी निमार्ताओं को मिलेगा। इससे न केवल उनकी उत्पादन लागत घटेगी, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, हैंडलूम वस्त्र, बांस उत्पाद, घरेलू खिलौने और आयुर्वेदिक दवाओं पर जीएसटी दरों में राहत दी गई है, जो ग्रामीण भारत और पारंपरिक उद्योगों को एक नई ऊर्जा देगी। छोटे कारोबारियों को फायदा जीएसटी की दरों में हालिया बदलाव ने छोटे उद्योगों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। 2025 में कई सामानों पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं। मिसाल के तौर पर, 28 प्रतिशत के स्लैब से कई उत्पादों को 18 प्रतिशत और कुछ को 12 से 5 प्रतिशत तक लाया गया है। इससे उत्पादन की लागत कम होगी, खासकर हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर–फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में, जहां जीएसटी 12 से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि छोटे कारोबारियों को कच्चा माल सस्ता मिलेगा, उनकी लागत 7–8 प्रतिशत तक कम होगी, और वे बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इस कदम से न सिर्फ उत्पादन सस्ता होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी और अन्य सामानों पर जीएसटी 28 से 18 प्रतिशत होने से उनकी कीमतें 7–8 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, खासकर ऑटो, कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में। नतीजतन, छोटे उद्योगों की के सामान की बिक्री बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी जीएसटी में कटौती का एक और बड़ा फायदा निर्यात के क्षेत्र में दिखेगा। कम टैक्स से भारतीय उत्पादों की कीमतें वैश्विक बाजार में और प्रतिस्पर्धी बनेंगी। खासकर लेदर और फुटवेयर जैसे निर्यात–आधारित उद्योगों को इससे खासा लाभ होगा। ये क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, और इनकी मजबूती से ग्रामीण और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स जैसे क्षेत्रों में कारीगरों को सस्ता कच्चा माल और बेहतर मुनाफा मिलेगा, जिससे उनकी आजीविका सुधरेगी। वोकल फॉर लोकल का नारा भारत विविधताओं वाला देश है,जहां हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, कारीगरी, उत्पाद और संस्कृति है, लेकिन वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के लोकल उत्पादों की उपेक्षा होती रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए भारत सरकार ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो आत्मनिर्भर भारत की नींव रखता है वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्थानीय उत्पादों के लिए आवाज उठाना और उनका समर्थन करना।

राशिफल

मेष :– विचारों की अस्थिरता आपको उलझनपूर्ण परिस्थिति में डालेगी। नौकरी–व्यवसाय के क्षेत्र में स्पर्धायुक्त वातावरण रहेगा। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। प्रवास की संभावना है।

वृषभ :– मन की दुविधा ठोस निर्णय पर आने से रोकेगी जिससे हाथ आए अवसर आप खो देंगे। झक्की व्यवहार के कारण संघर्ष में उतरने की संभावना है। नए कार्य के लिए दिन अच्छा नहीं है।

मिथुन :– आज का दिन लाभदायक साबित होने की आशा रख सकते हैं। सुबह से ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होगा। आर्थिक लाभ मिलने के साथ–साथ कहीं से गिफ्ट प्राप्त हो सकता है।

कर्क :– शरीर और मन में बेचौनी और अस्वस्थता का अनुभव होगा। मन की संदिग्धता और दुविधा आपकी निर्णयशक्ति को कसौटी के शिखर पर चढ़ाएंगे। वाद–विवाद से दूर रहें।

सिंह :– आज के दिन आपको विविध लाभ मिलने की संभावना है। ऐसे समय में मन का ढीलापन आपको लाभ से वंचित न कर दे, इसका ख्याल रखें। पदोन्नति और आय वृद्धि का योग है।

कन्या :– नए कार्य शुरू करने के लिए निर्मित योजनाओं को अमल में लाने का आज उत्तम समय है। व्यापार में लाभ होगा। बकाया वसूली के पैसे वापस मिलेंगे। पिता की तरफ से लाभ होगा।

तुला :– लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक स्थान की मुलाकात होगी। विदेश यात्रा के लिए अनुकूलता रहेगी। फिर भी आपको संतान और स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। धन का खर्च होगा।

वृश्चिक :– आज का दिन सावधानीपूर्वक बिताएं। नए कार्य शुरू न करें। क्रोध, आवेश और अनैतिक आचरण आपको कठिनाई में डाल सकते हैं। दुर्घटना से बचें।

धनु रू बौद्धिक, तार्किक, विचार–विनिमय और लेखन कार्य के लिए शुभ दिन है। भागीदारी में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ के सम्बंधों में अधिक घनिष्ठता रहेगी। मान–सम्मान मिलेगा।

मकर :– आज से आपके व्यापार–धंधे का विकास होगा। आर्थिक रूप से लाभदायक दिन होने से पैसे की लेन–देन में सरलता रहेगी। परिवार में सुख– शांति का माहौल रहेगा।

कुंभ :– आज आप संतान और अपने स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंतित रहेंगे। अपच, पेट–दर्द से परेशान होंगे। विचारों में तेजी से परिवर्तन मानसिक स्थिरता में खलल पहुंचाएगा।

मीन :– शारीरिक– मानसिक भय रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ वाद–विवाद होगा। माताजी का स्वास्थ्य खराब होगा। अनचाही घटनाओं से आपके उत्साह में कमी आएगी। अनिद्रा से परेशान रहेंगे।

सेवा पर्व को स्वच्छ उत्सव के रूप में भी मनाएगा वन विभाग

17 सितंबर से दो अक्टूबर तक विभाग चलाएगा विशेष स्वच्छता अभियान
पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती (25 सितंबर) पर भी हर जनपद में होगा पौधरोपण
शासन स्तर पर नोडल अधिकारी बने सचिव पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन
वन विभाग ने विभाग स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) को नामित किया नोडल अधिकारी
जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराए जाएंगे आयोजन, बाघ मित्र, सारस मित्र, वेटैंलड मित्र आदि भी कार्यक्रम में होंगे शामिल

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व को वन विभाग स्वच्छ उत्सव के रूप में भी मनाएगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक विरोधी अभियान, पक्षी अभयारण्यों में खर–पतवारों की सफाई के लिए भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण आदि विषयों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने इस संबंध में मुख्यालय व जनपद स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं अभियान की देखरेख के लिए शासन व विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। शासन स्तर पर सचिव वन–पर्यावरण को बनाया नोडल अधिकारी 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक होने वाले सेवा पर्व के समन्वय व निगरानी के लिए शासन स्तर पर उप्र के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशांत शर्मा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं वन विभाग ने विभागीय स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) रामकुमार को आयोजन की सफलता के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी होगा पौधरोपण चौधरी ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती (25 सितंबर) को प्रत्येक जनपद में पौधरोपण कार्यक्रम होगा। वन विभाग की ओर से आमजन, संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों को पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। पं. उपाध्याय की जन्मदिवस पर एक घंटे का वृहद कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, एनजीओ, रोटरी–लायंस क्लब, ग्राम पंचायत सदस्यों, शिक्षकों, उद्योगपतियों, मेडिकल एसोसिएशन आदि को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही वन विभाग की सहयोगी संस्थाएं बाघ मित्र, सारस मित्र, वेटलैंड मित्र आदि भी इस कार्यक्रम की वाहक बनेंगी। 15 लाख पौधरोपण अभियान को भव्य बनाने को सौंपी गई जिम्मेदारी पौधरोपण महाभियान–2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि सेवा पर्व के दौरान प्रदेश में 15 लाख पौधरोपण होंगे। सेवा पर्व का शुभारंभ 17 सितंबर को होगा। इसमें सभी 34 नगर वन में कम से कम 100 पौधे रोपित किए जाएंगे। इसमें जनसहयोग, स्वयंसेवी संगठनों, स्कूलों, ईको क्लब, स्वयं सहायता समूह, सिविल सोसायटी आदि का भी सहयोग रहेगा। जिलाधिकारी, नगर विकास व अन्य विभागों से परामर्श कर स्थल का चयन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों, नदी के कैचमेंट, तालाबों के किनारे आदि स्थानों पर पौधरोपण अभियान को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोजन में महापौर, सांसद, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रहेगी। विभाग ने हर जनपद में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही नवाचार पर भी जोर दिया है।

आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम ने अवैध शराब बरामद कर एक अभियुक्त को भेजा जेल

राजधानी लखनऊ के कई क्षेत्रों में की गई सघन चेकिंग ,मचा हड़कंप
ढाबा संचालकों को शराब न पिलाये जाने की सख्त चेतावनी दी गई

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। आगामी महीने के त्योहारों को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी विभाग की प्रवर्तन टीम ने औचक छापेमारी करके अवैध शराब निर्माण ,बिक्री से संबंधित स्थल, होटल आदि संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर अवैध शराब को बरामद कर उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया .आबकारी अधिकारी ने बताया कि गाजीपुर, इंदिरानगर, मड़ेगंज, हसनगंज, आलमबाग , हुसैनगंज, पारा, ठाकुरगंज, आशियाना, कृष्णानगर, काकोरी, दुबग्गा आदि थानों के संदिग्ध ग्रामों, स्थानों पर छापामारी की जिसमें संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में 7 अभियोगों को पंजीकृत करते हुए 85 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई तथा 50 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इसी तरह की एक अन्य कारवाही में 'मुखबिर से सूचना मिली कि हाई ब्रांड की मदिरा बोतलों में निम्न ब्रांड की मदिरा भरकर उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ करुणेन्द्र सिंह सचान के नेतृत्व में कौशलेंद्र रावत आबकारी निरीक्षक, सेक्टर 7 लखनऊ एवं प्रदीप कुमार शुक्ल आबकारी निरीक्षक सेक्टर–8 लखनऊ मयस्टाफ द्वारा थाना हुसैन गंज अंतर्गत छितवा पुर पजवा के निकट एक मकान नम्बर 68/246 कल्लू पंडित गली छितवा पुर पजवा में दबिश दी गई . दबिश मौके से 01 अभियुक्त तथा विभिन्न ब्रांडों की खाली बोतल(750ml) ,अद्धे (375ml) समेत नकली ढक्कन , नकली क्यू आर कोड व लगभग 3 लीटर अवैध शराब बरामद हुई । उक्त के संबंध में थाना हुसैनगंज में आबकारी व BNS की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मौके से मिले अभियुक्त राम पाल पुत्र राम लखन पाल निवासी–68/246 कल्लू पंडित गली छितवा पुर पजवा थाना– हुसैन गंज लखनऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।' साथ ही विजय राठी, आबकारी निरीक्षक, सेक्टर 9, शिखर मल्ल, आबकारी निरीक्षक सेक्टर 6, अभिषेक सिंह, आबकारी निरीक्षक, सर्किल 4, लखनऊ मय स्टाफ द्वारा सीतापुर लखनऊ मार्ग पर गुजरने वाले ट्रकों, टैंकरों आदि भारी वाहनों और अन्य छोटे कमर्शियल एवं प्राइवेट वाहनों की देर रात्रि को चेकिंग की गई तथा हाईवे और शहर स्थित ढाबों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। ढाबा संचालकों को शराब न पिलाये जाने की सख्त चेतावनी दी गई।

संक्षिप्त

जाली पेपर से लोन कराने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार, जीन साथी भी पकड़े गए

संवाददाता

लखनऊ। यूपी एसटीएफ ने साइबर फ्रॉड करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरोह लखनऊ समेत आस–पास के जिलों में कूटरचित दस्तावेजों और बैंक कर्मचारियों की आईडी हैक करके मुद्रा लोन और ऑटो लोन पास कराकर करोड़ों रुपए हड़प चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड गौरव सिंह (ब्रांच हेड, यूनियन बैंक जानकीपुरम), नावेद हसन, अखिलेश तिवारी और इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। आरोपियों ने मिलकर दर्जनों फर्जी फर्म बनाई और उन्हीं के खातों में लोन का पैसा ट्रांसफर कराते थे। राज बहादुर गुरुंग नामक व्यक्ति को 2–3 लाख रुपए के लोन की जरूरत थी। वह गैंग के इंद्रजीत सिंह के सम्पर्क में आया। इंद्रजीत ने उसे बैंक मैनेजर गौरव सिंह से मिलवाया और कई कागजों पर साइन करवा लिए। कुछ महीनों बाद उसके फोन पर ईएमआई का मैसेज आया तो पता चला कि उसके नाम से 24.8 लाख रुपए के दो लोन पास हुए हैं। एक 9.8 लाख का मुद्रा लोन और दूसरा 15 लाख का कार लोन था। एसटीएफ ने राज बहादुर गुरुंग की शिकायत पर 13 सितंबर को न्यू हजरतगंज अपार्टमेंट, ओमेक्स सिटी (थाना सुषांत गोल्फ सिटी) से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 5 मोबाइल, एक डेस्कटॉप, 268 फर्जी दस्तावेजों की छायाप्रति, नकली आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चेकबुक, 4 कारें, प्रिंटर और 50,750 नकद बरामद किए।नावेद और अखिलेश फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इंद्रजीत फील्ड से कस्टमर लाकर उनके दस्तावेजों पर फोटो और सिग्नेचर बदलकर फाइल तैयार करता था। गौरव सिंह अपनी अथॉरिटी और अन्य बैंक कर्मचारियों की आईडी से लोन अप्रूव कर देता था। लोन की राशि फर्जी फर्मों के खातों में आती और कैश निकालकर आपस में बांट ली जाती थी। गिरोह 2015 से सक्रिय है और अब तक करीब 20 गाड़ियां फाइनेंस कराई जा चुकी हैं। आरोपियों ने कई बैंकों से फर्जी तरीके से लोन पास कराकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। लखनऊ में चारों आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ ने जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फोरेंसिक परीक्षण कराने और गिरोह के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

एनडीए की परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी, 3 मिनट देर सेंटर पहुंचने पर लौटाए

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में रविवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (एनडीए एंड एनए) की प्रवेश परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही हैं। मौके पर पुलिस बल के साथ में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। इस दौरान अमीनाबाद स्थित सिंधी विद्यालय गर्ल्स इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को तय समय से 3 से 5 मिनट की देरी पर पहुंचने पर एंट्री नहीं दी गई। इस पर लोग नाराज हो गए। अजीत तिवारी ने कहा कि बच्चे को टेस्ट दिलवाने के लिए लेकर आए थे। तीन मिनट की देरी हुई तो विद्यालय के लोगों ने प्रवेश नहीं दिया। इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि अंदर गई तो फोटो के लिए बोला गया तो बाहर फोटो लेने आई अंदर से गेट बंद कर दिया गया। मौके पर कई लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। नेशनल पीजी कॉलेज के सेंटर में भी बड़ी संख्या में लोग टेस्ट देने पहुंचे। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। सीडीएस परीक्षा 10 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा तीन पालियों में सुबह 9.00 बजे से 11.00 बजे तक, दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक, शाम 4.00 बजे से 6.00 बजे तक आयोजित हुई। एनडीए–एनए की परीक्षा 21 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा दो पालियों में हुई। सुबह 10.00 बजे से 12.30 बजे तक, दोपहर 2.00 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन

मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, लखनऊ में सीरत-उन-नबी सम्मेलन आयोजित किया गया

संवाददाता

लखनऊ। दस दिवसीय सीरत–उल–नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अभियान के समापन दिवस पर, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, जामिया मस्जिद मुंशी पुलिया, लखनऊ में मौजूदा हालात में पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की मिसाल का मतलब शीर्षक से सीरत–उल–नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता अलीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निदेशक डॉ. अशहद जमाल नदवी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सूरह अल–अंबिया की तिलावत और जनाब मुफ्ती अली नईम रजी द्वारा इसकी व्याख्या से हुई। इस अवसर पर मौलाना ओबैदुर्रहमान अजहर और डॉ. कल्ब सिब्तैन नूरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने अपने भाषणों में कहा कि पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से प्रेम और उनके प्रति सम्मान धर्म का अभिन्न अंग हैं, इनके बिना धर्म अधूरा है। आज के हालात में, अगर हम अपने भाइयों और गैर–मुस्लिमों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, तो हमें प्राचीन पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के आदर्शों को अपनाना होगा। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की जीवनी केवल ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। उनकी शिक्षाएँ उपासना से लेकर जीवन के हर पहलू और व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामूहिक जीवन तक, हर पहलू पर प्रकाश डालती हैं। उनके आदर्श, न्याय, करुणा, धैर्य, विनम्रता और क्षमाशीलता हर युग के लिए आदर्श और प्रकाश स्तंभ हैं। वक्ताओं ने आगे कहा कि वर्तमान घरेलू, सामाजिक और वैश्विक समस्याओं का एकमात्र समाधान पवित्र पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सुंदर उदाहरण में निहित है। यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें उस नैतिक और आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता है जो पवित्र पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जीवन और चरित्र पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसका संकलन सोसाइटी की कार्यकारी परिषद के सदस्य श्री खुशतर जलीस अहमद ने किया है। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने इससे पहले इस्लाम का इतिहास शीर्षक से कई पुस्तकें लिखी हैं। अल्लाह तआला उन्हें इस सेवा का सवाब दे। आमीन। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष काजी अहमद रजा ने अंत में सभी उपस्थित लोगों और विशेष रूप से अतिथि वक्ताओं का धन्यवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि हम गहराई से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सीरत–उन–नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और अस्वातुन्न–मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ही वह स्रोत हैं जिनसे सामाजिक सुख और कल्याण के स्रोत प्रवाहित होते हैं। अंत में, उन्होंने लोगों को ईद मिलादुन्नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बधाई दी और कहा कि यदि ईश्वर ने चाहा तो सोसाइटी भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम और धार्मिक प्रकाशन आयोजित करती रहेगी।

स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने काटा फीता

संवाददाता

लखनऊ। एनबीआरआई लखनऊ में दो दिवसीय सीएसआईआर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का रविवार को डिप्टी सीए ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर शुरुआत की। कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन, टेक्नोलॉजी शो और स्टार्टअप पिच सेशन का आयोजन होगा। इसमें सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। कॉन्क्लेव को ऑर्गनाइज कर रहे एनबीआरआई के निदेशक डॉ.अजीत कुमार शासनी ने बताया कि इसका मकसद नए स्टार्टअप, रिसर्चर, उनके नवाचारों, उद्योग जगत के दिग्गजों, उद्यमियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। एनबीआरआई के निदेशक डॉ.अजीत कुमार शासनी ने बताया इस कॉन्क्लेव का मकसद उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ में नवाचार के लिए माहौल बनाना है। इस सम्मेलन के जरिए फूलों की खेती, हर्बल उत्पादों और कृषि से संबंधित स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है। इससे हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस कॉन्क्लेव में एनबीआरआई के अलावा सीएसआईआर, सीडीआरआई और आईआईटी आर भी शामिल होंगे। सीमैप के लखनऊ के इन चारों संस्थानों की संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। सीएसआईआर सीमैप की ओर से जम्मू, हैदराबाद और मुंबई में सफल आयोजन के बाद अब लखनऊ में यह चौथा कॉन्क्लेव है। राजधानी के चारों सीएसआईआर संस्थानों की ओर से बड़ी संख्या में नवाचारों के प्रदर्शन के अलावा लगभग 50 स्टार्टअप्स और इनके उत्पादों के स्टॉल लगेंगे। सीमैप और एनबीआरआई के एरोमा और फ्लोरीकल्चर मिशन से जुड़े कुछ ट्राइबल कृषकों के साथ ही लगभग 200 किसान यहां शिरकत करेंगे।

राजाभैया के पीआरओ रहे राजीव यादव की कुर्क होगी सम्पत्ति

गैंगस्टर के तहत होगी कार्रवाई

संवाददाता

लखनऊ। जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 (1) की कार्रवाई करते हुए सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के करीबी राजीव यादव व शराब माफिया सुधाकर सिंह के करीबी शेखर सिंह की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक अधिकारी राजीव की 82 लाख और शेखर की पांच लाख की संपत्ति कुर्क करेंगे।जिला प्रशासन के अनुसार सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव गैंग के लीडर के रूप में मानिकपुर थाना क्षेत्र के गोतनी निवासी राजीव यादव उर्फ राजू की जमीन व चार पहिया वाहन को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जो उसने आपराधिक कृत्यों से प्राप्त की है। राजीव पर संग्रामगढ़ थाने में हत्या, गुंडा एक्ट, आर्म्स व गैंगस्टर समेत 16 मुकदमे दर्ज हैं। शराब माफिया सुधाकर सिंह के करीबी बाघराय के शकरदहा निवासी शेखर सिंह उर्फ राज प्रताप सिंह के खिलाफ कुंडा थाने में धोखाधड़ी व गैंगस्टर के दो केस दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार का कहना है कि आपराधिक कृत्यों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।राजीव यादव दो दशक पहले कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पीआरओ हुआ करता था। राजा भैया से दूरी के बाद उसने सपा का दामन थाम लिया। पार्टी में भले ही उसे कोई पद नहीं मिला हो लेकिन वह सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के करीबियों में शामिल है।

कांग्रेस की बैठक में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विरोध, युवा नेताओं ने डोरमेट पर मंत्री की तस्वीर चिपकाई

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में पहुंचने से पहले संगठन पदाधिकारियों ने सरकार के मंत्री और रायबरेली के नेता दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया। बैठक जिस सभागार में आयोजित थी, उसके द्वार पर एक विशेष डोरमेट बिछाया गया था। इस डोरमेट पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तस्वीर लगाई गई थी। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने बैठक में प्रवेश करने से पहले तस्वीर पर फूल चढ़ाकर विरोध जताया और फिर बैठक में शामिल हुए। बैठक से पहले कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने भी मंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिनेश प्रताप पहले बसपा में रहते हुए मायावती को मां कहते थे, फिर गाली दी। सपा में गए, मुलायम सिंह को भगवान कहा, फिर गाली दी। कांग्रेस में आकर प्रियंका गांधी से टिकट लिया और अब कांग्रेस को छोड़कर गाली दे रहे हैं। दीपक सिंह ने कहा कि ऐसे लोग सत्ता के भूखे हैं और "गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। युवा कांग्रेस का यह विरोध मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर लगातार दिए जा रहे बयानों को लेकर था। पदाधिकारियों का कहना है कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान का सवाल है और ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राहुल गांधी 10 सितंबर को दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। रास्ते में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। रायबरेली में राहुल गांधी की गुरुवार को योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से हॉट–टॉक हुई थी। इसका वीडियो आज सामने आया। इसमें राहुल कह रहे कि आप चर्चा को बीच में नहीं रोक सकते। इस पर मंत्री ने कहा–आपके कहने से मैं नहीं मानूंगा। प्रोसीडिंग नियमानुसार होनी चाहिए। दरअसल, राहुल ने कल जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की थी। इसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल हुए। बैठक में 42 पॉइंट पर चर्चा होनी थी।

दुर्गा स्वरूपा सम्मान समारोह का आयोजन

संवाददाता

लखनऊ। दुर्गा स्वरूपा सम्मान समारोह 2025 का भव्य आयोजन 14 सितम्बर को उर्दू अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ में दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन द्वारा सचिव रागिनी श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। इस गरिमामयी समारोह में 13 विशिष्ट व्यक्तित्वों को उनके क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विशिष्ठ अतिथि नम्रता पाठक, बिन्दु बोरा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने सभी विभूतियों को स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, सेलिब्रिटी गेस्ट रोनी शाह भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहाकि दुर्गा स्वरूपा फाउंडेशन उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उन्हें प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने सम्मानित होने वाली विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इन विभूतियों ने अपने दम पर मुकाम हासिल कर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। सम्मानित होने वालो में साहित्य क्षेत्र से विद्या बिंदु सिंह, प्रो. सुरेंद्र विक्रम, नवल कांत सिन्हा, अंबरीन जैदी (सैन्य लेखिका), खेल क्षेत्र से सैयद अली (हॉकी खिलाड़ी), उमेश प्रसाद (तैराक), सुनील चंद्र जोशी (टेबल टेनिस खिलाड़ी), रचना गोविल (एथलीट), कला व संस्कृति से सुनीता झिंगरान (गायिका), फरहाना फातिमा (अभिनेत्री एवं नृत्यांगना), संजोली पांडे (लोकगायिका), पद्मश्री नसीम बानो (चिकनकारी कलाकार), सामाजिक कार्य से अमित अग्रवाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दुर्गा स्वरूपा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से 9 युवा उद्यमियों को सम्मानित किया गया। 5 गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।

बंथरा में 15 साल की छात्रा लापता, युवक और उसकी बहन पर बहला–फुसलाकर ले जाने का आरोप

संवाददाता

लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। परिजनों ने उन्नाव जिले के पुरवा स्थित जगाथा, मंगत खेड़ा निवासी रजनीश और उसकी बहन नीलम पर अपहरण का आरोप लगाया है। घटना 11 सितंबर की दोपहर करीब 12 बजे की है। किशोरी कक्षा 10 की छात्रा है। पिता का आरोप है कि रजनीश कई महीनों से उनकी बेटी को बरगला रहा था। विरोध के बावजूद वह अपनी बहन के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग का झांसा देकर किशोरी को ले गया। परिजनों के अनुसार घर से 22 हजार रुपए नकद और महिला के सोने के जेवर भी गायब हैं। इनमें चेन, झुमकी और पायल शामिल हैं। काफी खोजबीन के बाद परिवार ने बंथरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है। किशोरी की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जल्द की जाएगी।

राज्यसभा के माननीय उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह ने मानव रचना में सरोकार की पत्रकारिता पर पुस्तक का अनावरण किया

बीएनई

देहरादून। राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ में "हरिवंश एक्सपेरिमेंट विद एडवोकेसी जर्नलिज़्मरू फ्रॉम एड्स टू एक्शन, वर्ड्स टू चेंज" पुस्तक का विमोचन किया। अपने मुख्य वक्तव्य में हरिवंश नारायण सिंह ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण जागरूकता, स्वास्थ्य अभियानों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देकर इन लक्ष्यों को साकार करने में सहायक है। उन्होंने कहा, "पत्रकारिता केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि यह चेतना निर्माण, वंचितों को आवाज़ देने और असमानताओं को दूर करने का माध्यम है। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में मुझे ऐल्विन टॉफलर के शब्द याद आते हैं—21वीं सदी के निरक्षर वे नहीं होंगे जो पढ़—लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे जो बदलाव के साथ स्वयं को ढाल नहीं सकते। आज के पत्रकारों को केवल कहानीकार नहीं, बल्कि तकनीक के साथ तालमेल बैठाने

वाले दक्ष पेशेवर बनना होगा।" उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे चुनौतियों को अपनाएँ, अपने कौशल को निखारें और समाज में परिवर्तन लाने वाले अग्रदूत बनें। सभा को संबोधित करते हुए मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ के कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय श्रीवास्तव ने हरिवंश नारायण सिंह जी के पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान की सराहना की और कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच ने एडवोकेसी पत्रकारिता को सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक सिद्ध किया है। डॉ. श्रीवास्तव ने मानव रचना शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि—"मानव रचना शैक्षणिक संस्थानों ने बढ़खल झील परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके माध्यम से सूख चुकी झील के जल स्तर को पुनर्जीवित किया गया। इसके अतिरिक्त हमने आसपास के दस गाँवों का संरक्षण लिया है ताकि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही समुदायों के उत्थान के लिए अनेक परियोजनाएँ और अभियान चलाए गए हैं।" इस अवसर पर हरिवंश नारायण सिंह ने विद्यार्थियों के साथ संवादात्मक सत्र में भाग लिया और भारत में एडवोकेसी पत्रकारिता के विकास एवं प्रभाव पर गहन विचार साझा किए। उन्होंने फ्रांस की क्रांति जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों का उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार नए विचारों ने समाजों को रूपांतरित किया और जनमानस को प्रभावित किया। इस सत्र का संचालन प्रसिद्ध उपन्यासकार और मीडिया सलाहकार नवीन चौधरी ने किया। "सरोकार की पत्रकारिता: फ्रॉम एड्स टू एक्शन, वर्ड्स टू चेंज" पुस्तक, वरिष्ठ लेखक ए. एस. रघुनाथ द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक प्रतिष्ठित पत्रकारों, विज्ञापन, मार्केटिंग और मीडिया पेशेवरों द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि जब पत्रकारिता को सरोकार, नैतिकता और तकनीकी अनुकूलनशीलता के साथ जोड़ा जाता है तो यह सामाजिक प्रगति और सतत विकास के लिए सबसे शक्तिशाली साधन बन जाती है। कार्यक्रम का आयोजन पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन डीन प्रो. (डॉ.) शिल्पी झा द्वारा आभार व्यक्त करने के साथ हुआ। उन्होंने सभी गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों और योगदानकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और मीडिया व संचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं मूल्य—आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ के संकल्प को दोहराया।

हिंदी दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन एवं सुलेख प्रतियोगिता

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। हिंदी भाषा की महत्ता और गौरव को जन—जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज जनपद कन्नौज के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों सहित राधा देवी आदर्श संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय, गुरसहायगंज तथा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तिर्वा आदि विद्यालयों में हिंदी दिवस बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्र—छात्राओं ने कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, वाद—विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रतिभाग कर हिंदी के प्रति अपने प्रेम और लगाव को अभिव्यक्त किया। साथ ही सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने सुंदर हस्तलिपि और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हुए हिंदी भाषा की गरिमा को नए आयाम प्रदान किए। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, आचार्यों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए छात्रों से अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व और सम्मान की भावना बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत विजयी छात्र—छात्राओं को

पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया तथा सभी को हिंदी भाषा के प्रति और अधिक जागरूक एवं दक्ष बनने के लिए प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और राष्ट्र की एकता की मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि सुलेख प्रतियोगिता जैसी गतिविधियाँ न केवल छात्रों में भाषा—प्रेम को बढ़ाती हैं, बल्कि अनुशासन, एकाग्रता और सृजनात्मकता के विकास में भी सहायक होती हैं।

सहकारिता से बदलेगी हिमालयी राज्यों की तकदीर: डॉ. धन सिंह रावत

शिमला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में डॉ रावत ने रखी अपनी बात कहा, सहकारी बैंकों में व्यावसायिक नवाचार पर साझा प्रयास करेंगे दोनों राज्य

बीएनई

शिमला/देहरादून। हिमालयी राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच सहकारिता ऐसा माध्यम है, जो यहां की तकदीर बदल सकता है। इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और साझा प्रयास आवश्यक हैं। यह बात सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा शिमला में आयोजित राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में कही। डॉ. रावत ने कहा कि हिमालयी राज्यों की परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां की भौगोलिक विषमताएं विकास में कई बार बाधा बनती हैं, लेकिन सहकारिता ऐसा सशक्त माध्यम है, जो इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर ग्राम्य जीवन, महिला सशक्तिकरण, कृषि, दुग्ध उत्पादन तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों को नई दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलकर सहकारी बैंकों एवं समितियों में व्यावसायिक नवाचार पर काम करेंगे, इसके लिये दोनों राज्य ठोस कार्ययोजना तैयार करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' मंत्र को आत्मसात करते हुए बहुआयामी कार्ययोजनाएं लागू की हैं। इसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत अब तक 11,19,852 लाभार्थियों और 6,251 स्वयं सहायता समूहों को 6812 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया है। सहकारी समितियों और बैंकों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और माधो सिंह भंडारी सहकारी सामूहिक खेती योजना के माध्यम से किसानों और महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही मिलेट मिशन के अंतर्गत मण्डुवा, झंगोरा, रामदाना जैसी स्थानीय फसलों को उचित मूल्य देकर किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉ. रावत ने कहा कि सहकारी बैंकों में व्यावसायिक नवाचार को प्रोत्साहित कर उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों की भांति सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिगत कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड कॉपरेटिव फेडरेशन द्वारा कंप्लीट वेल्यू चेन की स्थापना कर स्थानीय स्तर पर रेशमी वस्त्रों को दून सिल्क ब्रांड नाम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी बाजार में बड़ी मांग है। डॉ रावत ने कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये राज्य सरकार सहकारिता विभाग के माध्यम से 3 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेशभर में विभिन्न थीमों पर सहकारी मेलों का आयोजन कर रही है। जो सहकारिता के विस्तार को नया आयाम देंगे साथ ही किसानों, काश्तकारों, कारीगरों, युवाओं और महिला समूहों को बाजार भी उपलब्ध करायेंगे। सम्मेलन में देशभर के सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, आरबीआई, नाबार्ड, अमूल, इफको, नाफेड, एनसीडीसी समेत विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेरठ में हार्टफुलनेस मेडिटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन अरुण गोविल के करकमलों द्वारा संपन्न

बीएनई

देहरादून। मेरठ स्थित हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर में तीन दिवसीय निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं सांसद श्री अरुण गोविल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ अनुपम अग्रवाल, क्षेत्रीय समन्वयक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदीप शर्मा, जिला समन्वयक मेरठ भी मंच पर उपस्थित थे। अपने प्रेरणादायक संबोधन में गोविल ने ध्यान के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा : "रोज़ाना केवल बीस मिनट ध्यान करने से तनाव और थकान से मुक्ति मिल सकती है। हमारा मन चंचल होता है और उसमें अनचाही छवियाँ आती रहती हैं। जब हम ध्यान के समय अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इन विचारों से छुटकारा पाना सरल हो जाता है। हृदय से हमारा तात्पर्य केवल भौतिक हृदय नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश से है।" उन्होंने यह भी कहा कि एक सच्चे गुरु की भूमिका आत्मिक प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है: "जब गुरु अपने शिष्य को ढूंढ़ लेता है तो आधा कार्य वहीं पूर्ण हो जाता है।" इस अवसर पर अरुण गोविल को अनुपम अग्रवाल द्वारा सम्मानित किया गया और "द होली तीर्थकरज़" पुस्तक भेंट की गई जो कि हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक एवं राम चंद्र मिशन के अध्यक्ष, आदरणीय दाजी की नवीनतम सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। कार्यक्रम में लगभग 1000 साधक एवं ध्यान—प्रेमी उपस्थित हुए। उद्घाटन सत्र में एक संगठित हार्टफुलनेस ध्यान सत्र भी आयोजित किया गया। ध्यान का तीन दिवसीय यह कार्यक्रम पूर्णतया निःशुल्क है और सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए सुलभ है। इच्छुक लोग स्थल पर पंजीकरण कर सकते हैं अथवा आमंत्रण पत्र पर दिए गए QR कोड के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। हार्टफुलनेस के बारे मेंरू हार्टफुलनेस एक वैश्विक ध्यान पद्धति है जो आंतरिक शांति, स्पष्टता, संतुलन, करुणा और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। इसकी शुरुआत बीसवीं सदी की शुरुआत में हुई थी और 1945 में श्री राम चंद्र मिशन के माध्यम से इसे संगठित रूप दिया गया। यह पद्धति 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त है और सभी पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और मत के लोगों द्वारा अपनाई जा सकती है। आ, हार्टफुलनेस पद्धति दुनिया के 160 से अधिक देशों में फैली हुई हैं और 5,000 से अधिक सेंटर, लाखों साधक तथा हज़ारों प्रशिक्षक स्वैच्छिक रूप से सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा यह पद्धति हज़ारों स्कूलों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट्स तथा विभिन्न सरकारी और गैर—सरकारी संस्थानों में भी अपनाई जा रही है।

संक्षिप्त

ब्रिटेन में सिख महिला का यौन उत्पीड़न, ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर ने की निंदा

एजेंसी

लंदन। ब्रिटेन की सिख सांसद प्रीत कौर गिल ने एक सिख युवती का यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना की निंदा की है। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा है कि वह इस हमले को नस्ली अपराध मानकर जांच कर रही है। प्रीत कौर गिल ने मंगलवार को इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के ओल्डबरी में हुए भयावह हमले पर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, 'ओल्डबरी में एक सिख महिला पर हुए भयावह हमले से मैं बेहद स्तब्ध हूं। यह एक अत्यधिक हिंसक कृत्य है लेकिन इसे नस्लीय भेदभाव के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि अपराधियों ने कथित तौर पर उससे कहा था कि श्वह यहां की नहीं है।'उन्होंने कहा, ''वह यहीं की है। हमारे सिख समुदाय और हर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का अधिकार है। ओल्डबरी या ब्रिटेन में कहीं भी नस्लवाद और स्त्री—द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी संवेदनाएं पीड़िता, उसके परिवार और सिख समुदाय के साथ हैं।

चावल नरम, गेहूं—चीनी मजबूत, खाद्य तेलों में घटत—बढ़त, दालों के बढ़े दाम

एजेंसी

नयी दिल्ली। बीते सप्ताह घरेलू थोक बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में मिला—जुला रुख देखा गया। चावल के दामों में कमी आई, जबकि गेहूं और चीनी की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। खाद्य तेलों के भाव में उतार—चढ़ाव रहा, और दालों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। सप्ताह के अंत में चावल की औसत कीमत 18 रुपये प्रति क्विंटल घटकर 3,759 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई। दूसरी ओर, गेहूं की कीमत में 10 रुपये की वृद्धि हुई और यह 2,859. 13 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। आटे के दाम भी 24 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर 3,334.63 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। खाद्य तेलों में सरसों तेल 68 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। मूंगफली तेल में 288 रुपये

और वनस्पति तेल में 112 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त देखी गई। सूरजमुखी तेल 70 रुपये और पाम तेल 140 रुपये प्रति क्विंटल की दर से महंगे हुए। हालांकि, सोयाबीन तेल की कीमत में 30 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई। दालों के बाजार में भी तेजी का रुख रहा। उड़द दाल 42 रुपये और मूंग दाल 38 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। तुअर दाल की कीमत में 8 रुपये की वृद्धि हुई, जबकि मसूर दाल 23 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हो गई। चना दाल के भाव लगभग स्थिर रहे। गुड़ और चीनी के बाजार में दो सप्ताह की नरमी के बाद फिर से तेजी देखी गई। गुड़ की औसत कीमत 54 रुपये और चीनी 29 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गई।

एनटीपीसी सिंगरौली, शक्तिनगर में हिंदी पखवाड़ा—2025 का शुभारंभ

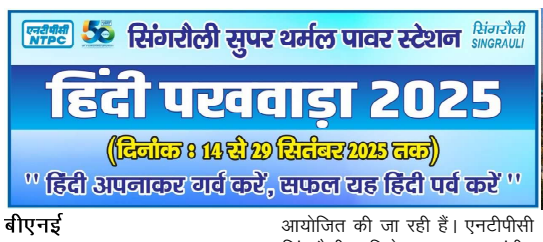

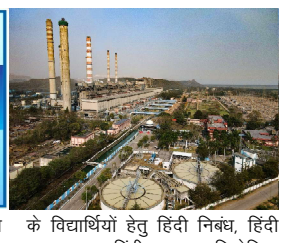

बीएनई

सिंगरौली। एनटीपीसी सिंगरौली, शक्तिनगर में दिनांक 14—29 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़ा—2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष राजभाषा हिंदी का व्यापक प्रचार—प्रसार एवं जन—जन तक हिंदी के संदेश को पहुचाने के उद्देश्य से दिनांक 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवम् 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है एवम् इसके तहत दो दिवसीय विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। एनटीपीसी सिंगरौली परियोजना प्रमुख संदीप नायक ने हिंदी को प्रोत्साहन हेतु हिंदी दिवस संदेश जारी करते हुए हिंदी की महत्ता पर अपने विचार रखे। उन्होंने हिंदी भाषा को स्वेच्छा से अपनाने का आग्रह किया ताकि हम सभी मिलकर गौरवशाली हिंदी भाषा की सांस्कृतिक पहचान से देश की भाषाई संस्कृति को समृद्ध कर सकें। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सिंगरौली, हिंदी भाषा को शीर्ष पर बनाए रखने हेतु निरंतर अभिनव पहल करती रहेगी। हिंदी पखवाड़े के दौरान आवसीय परिसर में संचालित विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु हिंदी निबंध, हिंदी काव्य पाठ, हिंदी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराए जाएंगे। विद्युत गृह के कर्मचारियों एवं गृहणियों हेतु भी निबंध लेखन, भाषण, हिंदी लघु चलचित्र, हिंदी प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। हिंदी पखवाड़ा के तहत ग्राम प्रधान, पत्रकार बंधु एवं शिक्षक गण के लिए भी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हिंदी पखवाड़ा के तहत नाट्य समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। हिंदी पखवाड़ा—2025 का समापन दिनांक—29.09.2025 किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय : शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती

625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग की मिली अनुमति

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्च शिक्षा में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की नई किरण लेकर आया है। 625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति भर्ती हेतु स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होने से महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती से खेल गतिविधियों को बढ़ावा इसी क्रम में क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती से पुस्तकालय होंगे सशक्त इसके अतिरिक्त ग्रंथपाल के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार का यह कदम महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे शिक्षण—अध्यापन का स्तर उन्नत होगा और संकायों की मजबूती सुनिश्चित होगी। इस पहल से विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। बेहतर संसाधनों और शिक्षकों की उपलब्धता से विद्यार्थियों की अकादमिक क्षमता और भी निखरेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महाविद्यालयों में रिक्त 700 पदों पर भर्ती होने से न केवल महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुदृढ़ होगा, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सीखने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह पहल आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सशक्त बनाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति इसी दिशा में एक बड़ा निर्णय है। इस पहल से एक ओर जहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी। वित्त विभाग द्वारा दी गई यह अनुमति भविष्य की पीढ़ी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा विगत 21 माह में महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों, आदिम जाति विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य विभिन्न विभागों के अनेक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री साय की घोषणा के अनुरूप शिक्षकों के 5000 पदों सहित अन्य पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तकनीक और प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इन सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति का बेहतर उपयोग होगा और प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

नेपाल में सुशीला कार्की की नियुक्ति से चीन खुश, आधिकारिक तौर पर दी बधाई, कहा—और गहरी होगी पुरानी दोस्ती

एजेंसी

बीजिंग। नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को चीन ने आधिकारिक तौर पर बधाई दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि नेपाल और चीन के बीच पुरानी और गहरी मित्रता है और बीजिंग हमेशा काठमांडू के फैसलों का सम्मान करता है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने बीते शुक्रवार को शपथ ली थी। इससे पहले नेपाल में एक हफ्ते तक हिंसक विरोध—प्रदर्शन चले थे, जिनके बाद उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चीन, मैडम सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता है। चीन और नेपाल के बीच पुरानी मित्रता है और हम नेपाल के लोगों के फैसले का सम्मान करते हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743